

[2023] 8 एस. सी. आर 1139

गुजरात राज्य ई. टी. सी. v.

/

चूड़ामणि परमेश्वरन अय्यर और ए. एन. आर. ईटीसी। (2023 की आपराधिक अपील संख्या 1963-64)

/

17 जुलाई, 2023

[जे. बी. पारदीवाला और

प्रशांत कुमार मिश्रा, जे. जे.]

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 -एस 69-एस के आह्वान के अंतर्गत जारी किए गए समन।438, तलब किए गए व्यक्ति द्वारा सी. आर. पी. सी.-की अनिवार्यता-आयोजित:यदि किसी व्यक्ति को यू/एस बुलाया जाता है।69, 2017 उसके बयान को दर्ज करने के उद्देश्य से अधिनियम, एस का प्रावधान।438, Cr.PC को लागू नहीं किया जा सकता है-समन किया गया व्यक्ति मुकदमे से पहले की गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा प्राप्त करने का एकमात्र तरीका उच्च न्यायालय के यू/अनुच्छेद 226 के अधिकार क्षेत्र को लागू करना है-वर्तमान मामले में उत्तरदाताओं ने ठीक यही किया-उच्च न्यायालय के समक्ष यू/अनुच्छेद 226 के तहत आपराधिक आवेदन दायर करके, उत्तरदाताओं ने अपीलार्थी को निर्देश देने की मांग की कि वह एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें गिरफ्तार न करे।69(1), 2017 अधिनियम-यह, संक्षेप में, अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना थी-हालाँकि, समन के स्तर पर, बुलाया गया व्यक्ति एस का आह्वान नहीं कर सकता है।438, सी. आर. पी. सी.-जी. एस. टी. अधिनियम के अंतर्गत एक सशक्त प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति वैधानिक है और आम तौर पर रिट न्यायालय को ऐसी शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए-आक्षेपित आदेश संबंधित प्राधिकारी को 8 सप्ताह के भीतर न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश देता है और उत्तरदाताओं को आवश्यक कदम उठाने के लिए दो और सप्ताह का समय देता है यदि किसी भी आशंका की आवश्यकता थी और यदि वे अपने दायित्व को पूरा करने के लिए तैयार नहीं थे, तो अलग रखें-हालाँकि, दोनों उत्तरदाताओं को अपने बयान दर्ज करने के लिए अधिकारियों के सामने पेश होने का एक और अवसर दिया जाता है-उनकी विफलता पर, विधि के अनुसार आगे बढ़ने का अधिकार-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.438-भारत का संविधान-अनुच्छेद 226-केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 -s.145-वित्त अधिनियम, 1994 -एस. 83.

/

/

/

/

/

भारत का संविधान-अंतर्गत 226-गिरफ्तारी से पहले सुरक्षा के लिए आवेदन-आयोजित:उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 226 के तहत गिरफ्तारी-पूर्व सुरक्षा के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए कोई रोक नहीं है, हालांकि, इस तरह की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए-अग्रिम जमानत के लिए याचिका और अग्रिम जमानत के रिट के बीच एक मौलिक अंतर है।

/

1139 ए.

1140 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 8 एस. सी. आर.

किसी अधिकारी को गिरफ्तारी न करने का निर्देश देना-आदेश की एक रिट केवल वैधानिक या अन्य कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए मजबूर करने के लिए होगी-किसी अधिकारी को अपने वैधानिक कार्य करने से रोकने के लिए आदेश की कोई रिट नहीं होगी-जब उच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 226 के अंतर्गत एक रिट आवेदन दायर किया जाता है, तो रिट अदालत का कर्तव्य है कि वह मामले के तथ्य की जांच करे और यह पता लगाए कि क्या रिट आवेदक का मामला असाधारण मामलों की श्रेणी में आता है।

/

कर्तार सिंह मामले में संकेत दिया गया।

कर्तार सिंह बनाम पंजाब राज्य **(1994) 3 एस. सी. सी. 569:**

[1994] 2 एस. सी. आर. 375-अनुसरण किया गया।

भारत संघ बनाम पदम नारायण अग्रवाल और अन्य।

/

(2008) 13 एससीसी 305:[2008] 14 एस. सी. आर. 17 9-पर निर्भर था।

पी. वी. रमण रेड्डी बनाम। भारत संघ **(2021) 2 एससीसी**

784 - संदर्भित किया गया।

संदर्भित निर्णय

/

[2008] 14 एस. सी. आर. 17

पर विश्वास किया

पैरा **13**

[1994] 2 एससीआर 375

पीछा किया।

पैरा **17**

(2021) 2 एस. सी. सी. 784

संदर्भित

पैरा **18**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील संख्या 1963-1964।

/

2018 के एस. सी. आर. ए. सं. 11010 और 11076 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 24.12.2018 के निर्णय और आदेश से।कानू अग्रवाल, सुश्री दीपानविता प्रियंका, माधव सिंहल, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

/

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., आर. पी. गुप्ता, मुकेश कुमार मारोरिया, प्रशांत सिंह प्रथम, वी. बालाजी, सुश्री मंजुला गुप्ता, शैलेश मडियाल, शरत नांबियार, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

/

आदेश

1. अनुमति दी गई।

2. निजी उत्तरदाताओं (मूल्यांकनकर्ताओं) की ओर से पेश विद्वान वकील ने कहा कि वह इस न्यायालय की सहायता करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि उनके मुवक्किल पिछले लगभग छह महीनों से उनके संपर्क में नहीं हैं।

/

गुजरात राज्य ई. टी. सी. v. चूड़ामणि परमेश्वरन अय्यर और ए. एन. आर. ईटीसी।

/

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें निजी उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील से किसी भी सहायता का कोई लाभ नहीं मिला।

4. हमने गुजरात राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील श्री कानू अग्रवाल को सुना है।

5. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से ऐसा प्रतीत होता है कि वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 70 (संक्षेप में "सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017") के अंतर्गत सेवा कर पर लागू किए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 145 (संक्षेप में "अधिनियम, 1944") के अंतर्गत प्रतिवादियों को दिनांक आई. डी. 1 पर समन जारी किया गया था, जिसमें उनसे एक मेसर्स अय्यर एंटरप्राइज मुंद्रा कच्छ के खिलाफ जांच के संबंध में पूछताछ के उद्देश्य से उपस्थित रहने का आह्वान किया गया था। संबंधित प्राधिकरण माल और सेवा कर देयता की कथित चोरी/वित्त अधिनियम 1994 और सी. जी. एस. टी. अधिनियम 2017 के प्रावधान के उल्लंघन के संबंध में प्रतिवादियों से पूछताछ करना चाहता है।

/

/

6. समन प्राप्त होने पर, प्रत्यर्थियों ने विभाग के संबंधित अधिकारियों के अंत में गिरफ्तारी की आशंका जताई।

/

7. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के समक्ष दो रिट आवेदन दायर किए गए, जो 2018 का विशेष आपराधिक आवेदन संख्या 11010 और 2018 का जवाब 11076 थे। दोनों रिट आवेदनों का निपटान एक सामान्य आदेश दिनांक 24.12.2018 द्वारा किया गया। आक्षेपित आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

/

"7. अभिवचनों की स्वैच्छिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जहां याचिकाकर्ता न्यायिक प्रक्रिया द्वारा स्वयं को सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने दें। संबंधित प्राधिकारी इसे 8 सप्ताह के समय में पूरा करेगा और यदि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी भी आशंका की आवश्यकता होती है, यदि वे अपने दायित्व को पूरा करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उन्हें आवश्यक कदम उठाने के लिए दो और

सप्ताह का अवसर दिया जा सकता है।याचिकाकर्ता संबंधित पुलिस स्टेशन के समक्ष 11/01 2019 को या उससे पहले उपस्थित होंगे।

/

/

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है।सीधी सेवा की अनुमति है। "

8. उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश से असंतुष्ट गुजरात राज्य वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष है।

/

1142

/

[2023] 8 एस सी आर।

/

9. पहली बार, इस न्यायालय ने 29.04.2019 पर मामले को उठाया और नोटिस जारी किया।नोटिस जारी करते समय, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर रोक लगाते हुए राहत प्रदान की कि न्यायिक प्रक्रिया को आठ सप्ताह की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

10. गुजरात राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने बताया कि एक प्रतिवादी को 14 समन जारी किए गए हैं।केवल एक बार, उत्तरदाताओं में से एक पूछताछ के उद्देश्य से पेश हुआ।इसके बाद, प्रत्यर्थियों में से कोई भी प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।अब 5 साल हो गए हैं कि जांच अभी भी लंबित है।उन्होंने आगे कहा कि उत्तरदाताओं से पूछताछ के बाद ही विभाग यह पता लगाने में सक्षम होगा कि कोई चोरी हुई है या नहीं और जिसके आधार पर शिकायत दर्ज करने आदि जैसी भविष्य की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

/

/

11. जिस तरह से उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थियों द्वारा दायर दोनों रिट आवेदनों का निपटारा किया है, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं।प्रतिवादियों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे समन का सम्मान करें और पूछताछ के उद्देश्य से प्राधिकरण के समक्ष पेश हों।

/

12. यह विधि की अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि जी. एस. टी. अधिनियम के अंतर्गत एक सशक्त प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति और इसे वैधानिक चरित्र कहा जा सकता है और आम तौर पर रिट न्यायालय को ऐसी शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि गिरफ्तारी की ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल उन मामलों में किया जा सकता है जहां आयुक्त या उनके प्रतिनिधि के पास यह विश्वास करने के कारण है कि व्यक्ति ने धारा 132 की उप-धारा (1) के खंड (ए) या खंड (बी) या खंड (सी) या खंड (डी) में निर्दिष्ट कोई अपराध किया है जो उक्त धारा के खंड (आई) या (बी) या उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अंतर्गत दंडनीय है।

/

/

13. जैसा कि इस न्यायालय ने भारत संघ बनाम पदम नारायण अग्रवाल और अन्य मामलों में कहा है। (2008) 13 एस. सी. सी. 305, (जो सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत सीमा शुल्क अधिकारियों की गिरफ्तार करने की शक्तियों के संदर्भ में था) ऐसी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग किसी अपराध के किए जाने के वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर किया जाना चाहिए और संबंधित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि गिरफ्तार किया जाना चाहता व्यक्ति ऐसे अपराध का दोषी रहा है।

/

14. पदम नारायण अग्रवाल (ऊपर) में इस न्यायालय ने इसे बहुत अच्छा बना दिया।

स्पष्ट करें कि आम तौर पर न्यायालय को गिरफ्तारी करने से पहले कोई शर्त नहीं लगानी चाहिए। यदि गिरफ्तारी से पहले कोई शर्त लगाई जाती है, उदाहरण के लिए संबंधित व्यक्ति को पूर्व सूचना देना आदि।

/

1143

गुजरात राज्य ई. टी. सी. v. चूड़ामणि परमेश्वरन अय्यर और ए. एन. आर. ईटीसी।

वैधानिक प्रावधानों को अप्रभावी, निरर्थक और अर्थहीन बना दिया जाएगा।

15. पदम के मामले में इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 44 और 45 के जवाब में की गई टिप्पणियां महत्वपूर्ण हैं।

नारायण अग्रवाल (ऊपर), जो इस प्रकार पढ़ता है:- “44. मामले में, प्रत्यर्थियों को केवल उनके बयान दर्ज करने के लिए अधिनियम की धारा 108 के अंतर्गत तलब किया गया था। उच्च न्यायालय इस तथ्य के प्रति सचेत और सचेत था। अतः इसने अभिनिर्धारित किया कि

परिस्थितियों में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन अपरिपक्व थे। तदनुसार, उत्तरदाताओं को सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देकर उनका निपटारा कर दिया गया। हालाँकि, न्यायालय वहाँ नहीं रुकी। इसमें कहा गया है कि भले ही सीमा शुल्क अधिकारियों को आवेदकों (यहां उत्तरदाताओं) के खिलाफ कोई गैर-जमानती अपराध मिलता है, उन्हें दस दिन की पूर्व सूचना के बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

/

/

/

45. हमारे निर्णय में, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, उपरोक्त निर्देशों में से किसी को भी विधि ी, वैध या विधि के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है। सबसे पहले, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एक व्यापक आदेश है जैसा कि इस न्यायालय की संविधान पीठ ने गुरबख्श सिंह के मामले में कहा था और किसी भी गैर-जमानती अपराध के संबंध में प्रतिवादियों को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। दूसरा, यह अवैध रूप से सीमा शुल्क अधिकारियों के अधिकार को एक ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की वैधानिक शक्ति का प्रयोग करने से रोकता है, हस्तक्षेप करता है और कम करता है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने दस दिन का पूर्व नोटिस देने की शर्त लगाई है, एक शर्त जो विधि द्वारा आवश्यक नहीं है। इसलिए, सीमा शुल्क अधिकारियों को जारी किए गए निर्देशों की सीमा तक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार किया जा सकता है और इसे इसके द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है।” (जोर दिया गया)

/

/

16. इस प्रकार, विधि की स्थिति यह है कि यदि किसी व्यक्ति को उसका बयान दर्ज करने के उद्देश्य से सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 69 के अंतर्गत तलब किया जाता है, तो दंड प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 438 के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है। हम कहते हैं कि चूंकि सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 69 (1) के अंतर्गत गिरफ्तारी की शक्ति लागू होने से पहले कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है और ऐसी परिस्थितियों में, समन किया गया व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 का आह्वान नहीं कर सकता है।

/

/

/

[2023] 8 एस सी आर।

/

अग्रिम जमानत। समन भेजे गए व्यक्ति द्वारा मुकदमे से पहले की गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा प्राप्त करने का एकमात्र तरीका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करना है। निस्संदेह, वर्तमान मामले में उत्तरदाताओं ने ठीक यही किया। प्रत्यर्थियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दो आपराधिक आवेदन दायर करके जो मांग की थी, वह अपीलार्थी को जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश था। यह, संक्षेप में, अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना की कुंजी है। हालाँकि, जैसा कि हमने ऊपर बताया है, समन के स्तर पर, तलब किया गया व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 का आह्वान नहीं कर सकता है।

/

/

17. कर्तार सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1994) 3 में यह न्यायालय

एस. सी. सी. 569 ने अनिश्चित शब्दों में कहा है कि गिरफ्तारी से पहले सुरक्षा का दावा न तो एक वैधानिक अधिकार है और न ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के जवाब के अंतर्गत गारंटीकृत अधिकार है। यद्यपि इस न्यायालय की संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत पूर्व-गिरफ्तारी संरक्षण के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए कोई बाधा नहीं है, फिर भी यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसी शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। अग्रिम जमानत के लिए याचिका और एक अधिकारी को गिरफ्तारी न करने का निर्देश देने वाले आदेश पत्र के बीच एक मौलिक अंतर है। परमादेश का एक रिट केवल वैधानिक या अन्य कर्तव्यों के प्रदर्शन को मजबूर करने के लिए होगा। किसी अधिकारी को अपना वैधानिक कार्य करने से रोकने के लिए कोई आदेश पत्र नहीं होगा। जब संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट आवेदन दायर किया जाता है, तो रिट अदालत का कर्तव्य है कि वह मामले के तथ्य की जांच करे और यह पता लगाए कि क्या रिट आवेदक का मामला कर्तार सिंह (ऊपर) में बताए गए असाधारण मामलों की श्रेणी में आता है। रिट न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या मैडमस की रिट जारी करके, यह सक्षम प्राधिकारी या उचित अधिकारी को उनके किसी भी वैधानिक कार्य को करने से रोकेगा।

/

/

/

18. उपरोक्त संदर्भ में, हम तेलंगाना उच्च न्यायालय के एक खंड पीठ के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं, जिसे अंततः इस न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (सी. आर. एल.) में पुष्टि की गई। 2019 के आदेश की संख्या 4430 दिनांकित 27.05.2019। हम मामले में एक फैसले का जिक्र कर रहे हैं।

/

पी. वी. रमण रेड्डी बनाम। भारत संघ की लिखित याचिका संख्या 4764

2019 और संबद्ध याचिकाओं पर 18 अप्रैल, 2019 को निर्णय लिया गया। उच्च न्यायालय द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं और हम उक्त टिप्पणियों से पूरी तरह सहमत हैं। उच्च ए की टिप्पणियाँ

/

1145

गुजरात राज्य ई. टी. सी. v. चूड़ामणि परमेश्वरन अय्यर और ए. एन. आर. ईटीसी।

न्यायालय सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 69 (1) और धारा 132 में पाई गई कुछ विसंगतियों के संदर्भ में आया। हम यहाँ प्रासंगिक टिप्पणियों को उद्धृत करते हैं:-

“34. यदि सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 अपने आप में (1) अपराधों का गठन करने वाले कृत्यों, (2) अभियोजन की प्रक्रिया और (3) दोषसिद्धि पर सजा के संबंध में एक पूर्ण संहिता है, तो आयुक्त, जो एक पुलिस अधिकारी नहीं है, की किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का आदेश देने की शक्ति भी अधिनियम में निहित प्रिस्क्रिप्शन से ही उत्पन्न होनी चाहिए। सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 69 (1) बहुत स्पष्ट रूप से आयुक्त की उस व्यक्ति की गिरफ्तारी का आदेश देने की शक्ति को दर्शाती है, जिसके बारे में उसे विश्वास है कि उसने ऐसा अपराध किया है जो संज्ञेय और गैर-जमानती है। इसलिए, हम नहीं जानते कि जिस व्यक्ति के बारे में आयुक्त का मानना है कि उसने सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (1) के खंड (एफ) से (एल) में निर्दिष्ट अपराध किया है, जो गैर-संज्ञेय और जमानती हैं, उसे कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 69 (1) ऐसे मामलों में गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान नहीं करती है। 35. यह तथ्य कि सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 69 (1) के अंतर्गत गिरफ्तारी की शक्ति केवल संज्ञेय और गैर-जमानती अपराधों तक ही सीमित है, धारा 69 की उप-धारा (2) द्वारा भी मजबूत किया गया है, जो गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने और 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए बाध्य करता है। गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति

को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करे और 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे, जो सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 69 की उप-धारा (2) और सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 132 (5) के अंतर्गत सह-संबंधित है, जो केवल संज्ञेय और गैर-जमानती अपराधों से संबंधित है।

/

/

/

/

/

36. लेकिन, दिलचस्प रूप से, सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 69 की उप-धारा (3) के खंड (ए) और (बी) पूरी तरह से केवल उन अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के मामलों से संबंधित हैं जिन्हें गैर-संज्ञेय और जमानती के रूप में इंगित किया गया है। "दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अधीन" वाक्यांश का उपयोग केवल उप-धारा (3) में किया जाता है, जो पूरी तरह से केवल उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद पालन की जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है जिसके बारे में माना जाता है कि उसने गैर-संज्ञेय और जमानती अपराध किया है।

/

/

1146 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 8 एस. सी. आर.

/

अपराध। जबकि उप-धारा (3) का खंड (ए) गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी को दो विकल्प देता है, अर्थात्, स्वयं जमानत देने या गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट की हिरासत में भेजने के लिए, खंड (बी) गैर-संज्ञेय और जमानती अपराधों के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने के उद्देश्य से उपायुक्त या सहायक आयुक्त (जी. एस. टी.) को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है।

/

37. दूसरे शब्दों में, भले ही सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 69 (1) आयुक्त को किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी का आदेश देने की कोई शक्ति प्रदान नहीं करती है, जिसने ऐसा अपराध किया है जो गैर-संज्ञेय और जमानती है, सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 69 की उप-धारा (3) जमानत देने, हिरासत में रिमांड और गैर-संज्ञेय और जमानती अपराध करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने की प्रक्रिया से संबंधित है। इस प्रकार, सी. जी.

एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 132 के साथ पठित धारा 69 की उप-धारा (1) और (3) के बीच कुछ विसंगति है।

/

/

38. सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 69 के साथ एक और कठिनाई यह है कि धारा 69 की उप-धारा (1) और (2) जो संज्ञेय और गैर-जमानती अपराधों के मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तारी और पेश करने की शक्ति से संबंधित है, "आई. डी. 1 के प्रावधानों के अधीन" वाक्यांश का उपयोग नहीं करती है। इस वाक्यांश का उपयोग केवल धारा 69 की उप-धारा (3) में उन अपराधों के लिए गिरफ्तारी और जमानत देने के संबंध में किया जाता है जो गैर-संज्ञेय और जमानती हैं, हालांकि गैर-संज्ञेय और जमानती अपराधों के संबंध में गिरफ्तारी की कोई शक्ति स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की जाती है।

/

/

39. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दंड प्रक्रिया संहिता एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 132 की उप-धारा (4) के अंतर्गत, धारा 132 (1) के खंड (ए) से (डी) के अंतर्गत अपराधों को छोड़कर अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराधों को गैर-संज्ञेय और जमानती बना दिया गया है, इसके अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 67 (10) में कुछ भी निहित है।

/

/

1147

गुजरात राज्य ई. टी. सी. v. चूड़ामणि परमेश्वरन अय्यर और ए. एन. आर. ईटीसी।

/

40. इसलिए, (1) इस तथ्य के आलोक में कि सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 69 (1) केवल उन व्यक्तियों की गिरफ्तारी को अधिकृत करती है जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध किए हैं, लेकिन सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 69 (3) गैर-संज्ञेय और जमानती अपराधों के संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को भी जमानत देने और जमानत देने की प्रक्रिया से संबंधित है और (2) इस तथ्य के आलोक में कि सी. जी. एस. टी. आयुक्त दंड प्रक्रिया संहिता जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 67 (10) के अंतर्गत तलाशी और जब्ती की शक्तियां प्रदान की गई हैं, उसी तरह जैसे कि आई. डी. 1, 1973 की धारा 165 में प्रावधान किया गया है, अतिरिक्त सॉलिसिटर

जनरल का तर्क है कि याचिकाकर्ताओं को जमानत देने और जमानत देने की प्रक्रिया से भी संबंधित है।

/

/

41. यद्यपि गवाहों को बुलाने और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से, दंड प्रक्रिया संहिता एस. टी. अधिनियम, 2017 के अंतर्गत जांच करने वाले उचित अधिकारी को एक दीवानी न्यायालय की तरह माना जाता है, अधिनियम में चार अन्य स्थान हैं, जहां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय दंड संहिता 1 का संदर्भ दिया गया है। वे हैं (1) भारतीय दंड संहिता 1 का संदर्भ। दंड प्रक्रिया संहिता एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 67 (10) के अंतर्गत तलाशी और जब्ती के संबंध में, (2) भारतीय दंड संहिता 1 का संदर्भ। धारा 69 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गैर-संज्ञेय और जमानती अपराध के संबंध में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत देने के संबंध में, (3) भारतीय दंड संहिता 1 का संदर्भ। धारा 132 में भारतीय दंड संहिता 1 का संदर्भ। इसलिए, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का तर्क कि सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 69 (3) को देखते हुए, याचिकाकर्ता गिरफ्तारी के खिलाफ सीमित संरक्षण पर वापस नहीं आ सकते हैं, जो Cr.P.C की धारा 41 और 41 ए में पाया जाता है, सही नहीं हो सकता है। जैसा कि पहले बताया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 6 दंड प्रक्रिया संहिता 41-ए को आई. डी. 1 में जोड़ा गया था। धारा 41 ए Cr.P.C की उप-धारा (3) अंतर्गत एक व्यक्ति जो उपस्थिति के लिए एक नोटिस का पालन करता है और जो समन अधिकारी के सामने उपस्थिति के लिए नोटिस का पालन करना जारी रखता है, उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वास्तव में, एक पुलिस पर लगाया गया कर्तव्य

/

/

/

/

/

1148 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 8 एस. सी. आर.

/

सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 70 (1) में धारा 41 ए (1) Cr.P.C के अंतर्गत किसी व्यक्ति को संज्ञेय अपराध के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाना काफी हद तक अंतर्निहित है। यद्यपि धारा 69 (1) जो आयुक्त को किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का आदेश देने की शक्तियां प्रदान करती है, उसमें वे सुरक्षा उपाय शामिल नहीं हैं जो Cr.P.C की धारा 41 और 41A में

शामिल हैं, हम सोचते हैं कि CGST अधिनियम की धारा 70 (1) आकस्मिकता का ध्यान रखती है।

/

42. किसी भी मामले में, जिस क्षण आयुक्त के पास यह मानने का कारण होता है कि किसी व्यक्ति ने अपनी गिरफ्तारी के लिए संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध किया है, तो हम सोचते हैं कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले सुरक्षा उपाय, जैसा कि Cr.P.C की धारा 41 और 41A में प्रदान किया गया है, को ध्यान में रखना होगा।

/

43. लेकिन, यह याद रखा जा सकता है कि Cr.P.C की धारा 41A (3) गिरफ्तारी के खिलाफ एक पूर्ण अपरिवर्तनीय गारंटी प्रदान नहीं करती है।पेशी की सूचनाओं के अनुपालन के बावजूद, एक पुलिस अधिकारी स्वयं धारा 41 ए (3) Cr.P.C के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दर्ज करने के कारणों के लिए गिरफ्तार करने का हकदार है।इस स्तर पर, हम दंड प्रक्रिया संहिता एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 41 ए (3) और 69 (1) के बीच भाषा में अंतर देख सकते हैं।Cr.P.C की धारा 41A (3) अंतर्गत "कारण दर्ज किए जाने चाहिए", एक बार जब पुलिस अधिकारी की राय हो कि संबंधित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।इसके विपरीत, धारा 69 (1) "विश्वास करने के कारण" वाक्यांश का उपयोग करती है।"दर्ज किए जाने वाले कारणों" और "विश्वास करने के कारणों" के बीच एक बड़ा अंतर है। "

/

/

19. हम अभी भी दोनों उत्तरदाताओं को अपने बयान दर्ज करने के उद्देश्य से अधिकारियों के सामने पेश होने का एक और मौका देने के लिए इच्छुक हैं।यदि प्रतिवादी उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो संबंधित प्राधिकारी के लिए विधि के अनुसार आगे बढ़ना खुला रहेगा।

/

20. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, दोनों अपीलों को अनुज्ञात किया जाता है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित 24.12.2018 दिनांकित सामान्य आदेश को दरकिनार कर दिया गया है।21. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

/

दिव्या पांडे

अपीलों की अनुज्ञात गई।

(सहायक: शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

/

